गन्ना मूल्य तय नहीं, गेंद कैबिनेट के पाले में

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : गन्ना समर्थन मूल्य तय करने के लिए मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका। लागत वृद्धि होने का तर्क दे किसान 350 रुपये प्रति क्विंटल दाम देने की मांग पर अड़े रहे तो वहीं चीनी मिल मालिकों का पक्ष रख रहे लोग भी राजी नहीं हुए। निर्णय अब मंत्रिमंडल की बैठक में होगा।

मंगलवार को योजना भवन में शाम पांच बजे से करीब दो घंटे चली गन्ना मूल्य निर्धारण संस्तुति समिति की बैठक में पक्ष विपक्ष में तर्क दिए गए। किसानों की ओर से किसान जागृति मंच के सुधीर पंवार ने मजदूरी की दरों में वृद्धि के अलावा खाद बिजली व पानी महंगा होने का तर्क दिया। उनका कहना था कि चीनी से डी-कंट्रोल खत्म करने के साथ मिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसान के खाते में दी जाए। रालोद के राजकुमार सांगवान ने कहा कि 350 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य किया जाए क्योंकि गत वर्ष भी कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की गई। मवाना के संतकुमार व लखीमपुर खीरी के कल्वे हसन ने गन्ना मूल्य को लेकर तमाम तर्क देकर 350 रुपये गन्ना मूल्य देने की मांग की और पेराई जल्द शुरू कराने का मुद्दा भी उठाया।

दूसरी ओर मिल मालिकान की ओर से उप्र शुगर मिल्स एसोसिएशन के दीपक गुप्तारा, पूर्वी उप्र चीनी मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य मिलों के प्रबंधक भी मौजूद रहे। गुप्तारा का कहना था कि बाजार में चीनी मिल के दामों का अनुपात देख कर गन्ना मूल्य तय हो। इस पेराई सत्र में भी दो किस्तों में भुगतान का प्रस्ताव रखा। पहली किस्त 220 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक न हो। वहीं नेशनल शुगर इंस्टीटयूट कानपुर के निदेशक चीनी मिलों को नजरिया बदलने की सिफारिश करते हुए कहा कि मिलों को इंटीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स में तब्दील करने की जरूरत है। प्रमुख सचिव चीनी उद्योग राहुल भटनागर ने दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। बैठक का संचालन गन्ना आयुक्त सुभाष चंद शर्मा ने किया।

- **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहूत बैठक में नहीं हो सका फैसला, किसान 350 रुपये दाम की मांग पर अड़े, मिल मालिकान राजी नहीं**

रिकवरी का टेक्निकल ऑडिट होगा

चीनी मिलों में गन्ने से कम रिकवरी से होने वाले नुकसान का टेक्निकल ऑडिट कराने की योजना है ताकि चीनी उत्पादन में कमी न आने पाए। किसानों को चीनी मिल मालिकों के माध्यम से प्राप्त होने वाली सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में पहुंचाने पर भी विचार किया जा रहा है।

DAINIK JAGRAN, 29/10/14

Pg - 11